जनसत्ता

नई पारी

भारी बहुमत से चुनाव जीत कर दुबारा सत्ता की कमान संभालने वाली भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार के मंत्रियों पर स्वाभाविक ही लोगों की नजर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य समारोह में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनकी सरकार में ज्यादातर पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया है। कुछ नए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों का चुनाव करते समय क्षेत्र, वर्ग आदि के साथ-साथ सहयोगी दलों का भी ध्यान रखा गया है। इस तरह मंत्रियों के चुनाव से उम्मीद जगी है कि सरकार इस बार भी तमाम क्षेत्रों में कामकाज सुचारु ढंग से चलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। आमतौर पर मंत्रिमंडल का गठन करते समय दलों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और करीबी लोगों का दबाव देखा जाता है, मगर नई सरकार के मंत्रिमंडल में यह दबाव नजर नहीं आता। चूंकि सरकार के कामकाज की जवाबदेही आखिरकार सत्ता के मुखिया पर आती है, इसलिए उसका दायित्व होता है कि वह ऐसे लोगों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपे, जो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार हों और सरकार के दृष्टिकोण तथा लक्ष्यों के अनुरूप काम कर सकें। फिर जब कोई सरकार अपनी दूसरी पारी शुरू करती है, तो पुराने सहयोगियों के कामकाज का भी मूल्यांकन करती है। अगर वह किसी मंत्री के कामकाज से संतुष्ट नहीं होती, तो उसे दुबारा जिम्मेदारी न सौंपने जैसे कठोर फैसले भी करने पड़ते हैं। इस तरह नई सरकार अपने मंत्रिमंडल के गठन में अधिक व्यावहारिक नजर आई है।

कई बार सरकारें दूरगामी लक्ष्य लेकर चलती हैं। कई ऐसी योजनाएं होती हैं, जिनके नतीजे एक-दो साल में नजर नहीं आते। उन पर सतत ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस तरह जब कोई पार्टी दुबारा सत्ता में आती है, तो उसे अपनी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं पर लगातार काम करने की जरूरत होती है। अगर पिछले कार्यकाल में उनमें कोई कमी रह गई है या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, तो उस दिशा में काम करने की जरूरत होती है। या फिर जिन क्षेत्रों में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा पाया होता है, उनमें नए सिरे से कार्ययोजना तैयार करनी होती है। पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, रोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की थीं। उनमें से कई के अपेक्षित नतीजे अभी आने हैं। ऐसे में जिन मंत्रियों ने लक्ष्य के अनुरूप काम किए, उन्हें जिम्मेदारी सौंपना लाजमी है। इससे बड़ा फायदा यह भी होता है कि जो व्यक्ति लगातार जिस क्षेत्र में काम करता आया हो, योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहा हो, उसे उस काम के हर पहलू का ज्ञान होता है और जब उसे दुबारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसके लिए परेशानी नहीं होती। वह सहजता से उस काम को करने में जुट जाता है। इस लिहाज से कई मंत्रियों को दुबारा सरकार में शामिल किया जाना सरकार का समझदारी भरा कदम कहा जाएगा।

भाजपा इस बार पिछले चुनाव से भी अधिक सीटों पर विजय हासिल कर सत्ता में आई है। इसका अर्थ है कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर भरोसा है। इस तरह नई सरकार पर जिम्मेदारियां पहले से कुछ अधिक बढ़ गई हैं। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों की चुनौतियों से पार पाना बड़ा काम माना जा रहा है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखना और उनकी जरूरतें पूरी करने का बड़ा दायित्व उसके कंधों पर है। यह काम भरोसेमंद, ईमानदार, कर्मठ और कुशल मंत्रियों के बल पर ही संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री कुशल प्रशासक हैं और वे जानते हैं कि किन लोगों के सहयोग से वे चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकते हैं। पिछले कार्यकाल में मंत्रिमंडल का गठन करते समय भी उन्होंने बड़ी सूझबूझ और पारदर्शिता के साथ सदस्यों का चुनाव किया था। युवा और ऊर्जावान लोगों को अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लोगों को उपकृत करने या फिर किसी तरह के दबाव में आकर मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाने के मोह में नहीं पड़ा गया। इस बार भी वही दृष्टि दिखाई दी है। सभी मंत्री अनुभवी और ऊर्जावान हैं, जो नए हैं, उन्हें अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। इस तरह ऊर्जा और अनुभव के मेल से बेहतर काम का भरोसा जगता है। फिर छोटा मंत्रिमंडल अधिक काम का सूत्र ज्यादा कारगर साबित होता है। इस तरह सरकार के अनावश्यक खर्चे भी बचते हैं। इस लिहाज से नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव बेहतरी की उम्मीद जगाता है।

जानलेवा परिसर

गुजरात के सूरत में एक कोचिंग संस्थान में लगी आग से करीब दो दर्जन बच्चों की मौत की त्रासद घटना लोगों के ध्यान से उतरी भी नहीं थी कि दिल्ली में इसी तरह का एक हादसा हो गया। गनीमत बस यह थी कि जिस इमारत में आग लगी, उसमें मौजूद लगभग पचास बच्चियों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन इससे एक बार फिर यही साफ हुआ है कि शिक्षा का कारोबार करने वालों के लिए प्राथमिकता केवल कमाई है। जो बच्चे उनके संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल कोई खास मायने नहीं रखता। वरना क्या वजह है कि जिस इमारत में चलने वाले हॉस्टल में पचास से ज्यादा बच्चियां रह रही हों, वहां आग लगने के हालात और उससे बचाव के इंतजाम नाकाफी थे? गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक रिहाइशी इमारत में चल रहे छात्रावास में अचानक आग लग गई। इमारत के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां तोड़ कर लड़कियों की जान बचाई गई। कुछ ने पहली मंजिल पर से ही नीचे छलांग दी। वहां बाद में पहुंची दमकल के जरिए आग बुझाई गई। शुरुआती तौर पर बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि उस मकान में हादसे की स्थिति में सुरक्षा इंतजामों को इस हालत में छोड़ दिया गया था कि आग लगने पर सबकी जान जा सकती थी। हालत यह है कि उस इमारत के जिस तलघर में शॉट सर्किट होने की बात सामने आई है, उसमें भी अवैध रूप से लड़कियों के रहने की जगह बनाई गई थी और आग लगने के बाद सबसे ज्यादा जोखिम में वही थीं।

विचित्र है कि जिस हादसे की प्रकृति इस कदर गंभीर थी कि वहां फंसे बच्चों के जिंदा जल जाने तक का जोखिम पैदा हो गया था, उसके संचालकों के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई होने की खबर नहीं है। जबकि इमारत में अवैध निर्माण से लेकर आग से बचाव के उपकरणों के मामले में भारी लापरवाही बरती गई थी। सवाल है कि क्या छात्रावास के संचालकों की लापरवाही तब कानूनी कार्रवाई के लायक मानी जाती जब सूरत जैसे हादसे में बच्चों की जान चली जाती? रिहाइशी इलाके में छात्रावास जैसी व्यावसायिक गतिविधि किस आधार पर चल रही थी? किसी व्यावसायिक गतिविधि और ज्यादा संख्या में लोगों की रिहाइश या आवाजाही वाली जगह पर हादसों की आशंका और वहां के सुरक्षा इंतजामों की जांच और निगरानी करना किसकी जिम्मेदारी है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मामूली लापरवाही की वजह से ही सूरत जैसे हादसे सामने आते हैं। अगर वक्त पर हर स्तर पर चौकसी नहीं बरती गई, तो इस तरह की जगहों पर रहने वाले विद्यार्थियों की जान हमेशा जोखिम में रहेगी।

कल्पमेधा

महान नेताओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देते हैं और उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।

-जवाहरलाल नेहरू

तंबाकू निषेध और चुनौतियां

रवि शंकर

तंबाकू सेवन और धूम्रपान से देशभर में हर घंटे करीब डेढ़ सौ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दुनिया में प्रति छह सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। विकासशील देशों में हर साल आठ हजार बच्चों की मौत अभिभावकों के धूम्रपान करने की वजह से होती है। दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

धूम्रपान विश्व की बड़ी समस्या बन कर उभरा है। धूम्रपान करने वालों की संख्या करोड़ों में है जो किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन किस कदर घातक हो सकता है, इसका अंदाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की उस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जिसमें बताया गया है कि पिछली यानी बासवीं सदी में तंबाकू सेवन से मरने वालों की संख्या दस करोड़ से ज्यादा थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर हालात नहीं बदले तो इक्कीसवीं सदी में इससे मरने वालों का आंकड़ा एक अरब के करीब पहुंच सकता है। भारत भी इसके असर से अछूता नहीं है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की बारह फीसद आबादी भारत में हैं। हालांकि, भारत में भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है, लेकिन लचर कानून-व्यवस्था और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण इस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है।

भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी जा चुकी है। इसका मकसद तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना है। देश में हर साल दस लाख लोगों की मौत तंबाकू का सेवन करने से होती है। सोलह की उम्र से कम चौबीस फीसद बच्चे किसी न किसी पड़ाव पर तंबाकू का सेवन कर चुके होते हैं, जबकि चौदह फीसद अब भी तंबाकू उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, 2016 मुताबिक भारत के 44.4 फीसद पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। करीब सात फीसद महिलाएं भी हर दिन तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में तंबाकू सेवन के मामले में लड़कियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं और लड़कियों में तंबाकू के प्रति बढ़ रहे शौक से गंभीर समस्या सामने आने के संकेत मिल रहे हैं। बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मेक्सिको और न्यूजीलैंड सहित दुनिया के डेढ़ सौ से ज्यादा देशों में किए गए सर्वे के मुताबिक लड़कियों में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति लड़कों के मुकाबले ज्यादा बढ़ रही है।

बाजार में नशा कई रूपों में उपलब्ध है। जैसे- बीड़ी, सिगरेट, गुटका, खैनी, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन व अन्य नशीली दवाएं आदि। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि तंबाकू की गिरफ्त में देश के युवा और बच्चे तेजी से आ रहे हैं जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं। युवाओं के इस चंगुल में फंसने के कई कारण हैं, जैसे- यार-दोस्तों की संगत, आधुनिक दिखने की चाह, फैशनेबल होने का दिखावा, बेरोजगारी या प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने पर होने वाले तनाव को कम करने की कोशिश या और दूसरे कारण। लेकिन धीरे-धीरे वे इसके आदी हो जाते हैं और इसके बिना रह नहीं पाते हैं। जबकि वे भलीभांति जानते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी इसे लेना अपनी शान समझते हैं। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार एक सिगरेट जिंदगी के ग्यारह मिनट व पूरा पैकेट तीन घंटे चालीस मिनट तक छीन लेता है। तंबाकू सेवन और धूम्रपान से देशभर में हर घंटे करीब डेढ़ सौ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दुनिया में प्रति छह सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। विकासशील देशों में हर साल आठ हजार बच्चों की मौत अभिभावकों के धूम्रपान करने की वजह से होती है। दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले में भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक तंबाकू या सिगरेट का सेवन करने वालों को मुंह का कैंसर की होने की आशंका सामान्य व्यक्ति के मुकाबले पचास गुना ज्यादा होती है। तंबाकू में पच्चीस ऐसे तत्त्व होते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इनक्यानवे फीसद मुंह के कैंसर तंबाकू से ही होते हैं। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के आधार पर इस समय दुनिया में हर साल पचास लाख से अधिक व्यक्ति धूम्रपान के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। यदि इस समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2030 में धूम्रपान से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अस्सी लाख सालाना से अधिक हो जाएगी। धूम्रपान करने वालों की औसत आयु पंद्रह वर्ष कम हो रही है।

आज दुनिया में कैंसर मौत का दूसरा बड़ा कारण है और धूम्रपान इस बीमारी को जन्म देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि फेंफड़े के कैंसर से ग्रस्त होने और सिगरेट का सेवन करने वाले पुरुषों में मृत्यु की संभावना सिगरेट का सेवन न करने वाले पुरुषों से तेईस गुना अधिक होती है, जबकि इस कैंसर से ग्रस्त होने की संभावना सिगरेट का सेवन करने वाली महिलाओं में सिगरेट का प्रयोग न करने वाली महिलाओं से तेरह गुना अधिक होती है। तंबाकू (सिगरेट) शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है और कैंसर का कारण बनता है।

बहरहाल, दुनियाभर में तंबाकू सेवन का बढ़ता चलन स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरा नहीं है, बल्कि इससे भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। विशेषकर यह निर्धन लोगों की निर्धनता में वृद्धि का भी बड़ा कारण है। अधिकांश देशों में धूम्रपान का सेवन धनी लोगों की अपेक्षा निर्धन लोगों में अधिक है और कुछ अवसरों पर यह भी देखने को मिलता है कि कम आय वाले लोग धूम्रपान का सेवन ज्यादा करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दुनियाभर में तंबाकू पैदा करने के लिए करीब तियालीस लाख हेक्टेयर (एक करोड़ एकड़) जमीन इस्तेमाल हो रही है। यह स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के एक सौ पच्चीस देशों में तंबाकू की खेती होती है। हर साल करीब साढ़े पांच खरब सिगरेटों का उत्पादन होता है और एक अरब से ज़्यादा लोग इसका सेवन करते हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत में सिगरेट का उत्पादन दस अरब सालाना का है। भारत में करीब तिहत्तर लाख किलो तंबाकू की पैदावार होती है। भारत तंबाकू निर्यात के मामले में ब्राजील, चीन, अमेरिका, मलावी और इटली के बाद छठे स्थान पर है। यह भी सच है कि तंबाकू विरोधी अभियानों पर दुनिया के देश जितना खर्च करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तंबाकू पर टैक्स लगा कर कमाते हैं। इससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है।

हालांकि अध्ययन यह भी बताते हैं कि सिगरेट का सेवन करने वाला हर व्यक्ति नशेड़ी नहीं बन जाता, लेकिन सिगरेट का सेवन करने वाले अधिकांश लोग बड़ी जल्दी नशे के आदी होने लगते हैं। वास्तव में सिगरेट नशेड़ी बनने के प्रवेश द्वार की भूमिका निभाती है। जाहिर है, सिगरेट का सस्ता होना, उस तक आसान पहुंच, कम आय वाले वर्ग एवं युवाओं में सिगरेट पीने के रुझान में वृद्धि ऐसे महत्त्वपूर्ण कारण हैं जो नशे की लत को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस आम जनमत को धूम्रपान के विनाशकारी प्रभावों से अधिक जागरूक बना कर लोगों को धूम्रपान के सेवन से बचाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इस मौके पर तंबाकू से बचाव का संकल्प समाज को करना होगा।

पूर्वाग्रहों के रंग

चंद्रकांता

दुनिया मेरे आगे

मां होना एक जैविक अनुभव है और मानवीय संवेदना का विस्तार करने वाली एक खूबसूरत भावना भी। जैविक रूप से प्रकृति ने केवल महिलाओं को यह सुविधा दी है कि वे एक नए जीवन को जन्म देकर इस संसार को उसे सौंप सकें। जो महिलाएं जैविक रूप से मां बनने की इच्छा रखती हैं, उनके लिए गर्भावस्था एक अनूठा उत्सव लेकर आती है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां गर्भाधान का यह अनन्य सुख लाखों-करोड़ों औरतों से उनकी कोमल संवेदनाओं और उनके 'आत्म' को छीन लेता है। कारण यह कि कहीं उन पर लड़का पैदा करने के लिए पितृसत्ता का दबाव है तो कहीं गोरा बच्चा पैदा करने की सामाजिक 'बाध्यता'! इसमें पैदा होने वाले बच्चे के रंग को लेकर घर-परिवार से लेकर समाज तक की उत्सुकता एक खास मानस और ग्रंथि को दर्शाती है। यानी बच्चा पैदा हो तो गोरा हो। सांवला हुआ तो सबके चेहरे पर निराशा छा जाती है। सच यह है कि गोरे रंग को लेकर 'सोशल कंडीशनिंग' की शुरुआत भारत में गर्भावस्था से ही हो जाती है, जब महिलाओं को घर के बुजुर्गों द्वारा गोरा बच्चा पैदा करने के लिए नारियल खाने और केसर वाला दूध पीने की सलाह दी जाने लगती है। हमारे समाज की एक आम हकीकत यही है।

लेकिन कभी जातीय सफाए या संहार के लिए खबरों में रहने वाला मध्य-पूर्व अफ्रीका का देश रवांडा पिछले दिनों एक खास घटना को लेकर चर्चा में रहा। रवांडा ने भारी तादाद में रंग गोरा करने वाली क्रीम, लोशन, साबुन और ब्लीच उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें अधिकतर ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिनमें शरीर की रंगत को हल्का करने वाला हाइड्रोक्विनन रसायन और मरकरी मिलाया जाता है। इन रसायनों के इस्तेमाल से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचता है और अवसाद जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। लेकिन बात केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। अफ्रीकी देशों में रंग गोरा करने वाले उत्पादों की भारी मांग है लेकिन आज उनमें हालात इतने अधिक खतरनाक हो गए हैं कि गर्भवती महिलाएं गोरा बच्चा पैदा करने के दबाव में अपने पेट पर भी सफेदी की क्रीम पोतने को विवश हैं।

जैविक रूप से त्वचा की रंगत एक तटस्थ कारक है। लेकिन बात केवल सौंदर्य की नहीं है। जब हम सामाजिक और सामरिक कारकों की पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि गोरा रंग आधिपत्य, प्रभुत्व और उपनिवेशवाद का प्रतीक है। भारत का संविधान किसी भी रूप में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। बावजूद इसके व्यावहारिक स्तर पर यहां के समाज में गोरे-काले रंग का विभेद संस्थागत है। यहां रंगत समाज में आपकी स्थिति, पद और प्रतिष्ठा को बहुत गहरे प्रभावित करती है। काला-गोरा रंग, लंबा-छोटा कद, टेढ़े-तीखे नैन-नक्श या सुडौल-स्थूल शरीर- इन सब बातों को लेकर किसी समाज का असहज होना भारी चिंता का विषय है।

आज हमारी पहचान वह बन गई है जो बाजार या समाज हम पर थोपता है। इस मकड़जाल से अमीर-गरीब और माध्यम वर्ग, सब समान रूप से प्रभावित हैं खासतौर पर स्त्रियां। खुद को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपनी पहचान या चयन को बाजार के आधार पर परिभाषित करने लगते हैं तो मामला सच में गड़बड़ है। हमारे समाज में ये सब अवधारणाएं इतनी संस्थागत हो चुकी हैं कि आम आदमी अपनी पहचान को इन्हीं आधारों पर परिभाषित करता है। जो भी इन रेडीमेड खांचों में फिट नहीं बैठता, समाज में उनकी चुटकी ली जाती है, 'बॉडी शेमिंग' की जाती है यानी शरीर को निशाना बना कर शर्मिंदा किया जाता है।

गोरेपन के विज्ञापन यह विश्वास दिलाते हैं कि गोरा होने से आत्मविश्वास बढ़ता है, रंगत विवाह में बाधा नहीं बनती, प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, सुस्त कॅरियर में चार चांद लग जाते हैं। जबकि हकीकत कुछ और है। ऐतिहासिक रूप से पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि 'सुर-असुर' या 'आर्य-अनार्य' की संस्कृति मूल रूप से गोरे और काले के भेद पर टिकी है। हम बचपन में जिन दादी-नानी की कहानियों, लोक कथाओं और किंवदंतियों को सुन कर बड़े होते हैं। वे हमारे दिमाग की स्थायी स्मृति में अपना घर कर लेती हैं और काला रंग हमारे जेहन में हमेशा के लिए विपर्यय बन जाता है। 'काला अक्षर भैंस बराबर', 'भैंस के आगे बीन बजाना', 'मुंह काला करना' जैसे मुहावरे हमारे समाज की सामूहिक सोच का एक नमूना भर हैं। यही काम हमारी पाठ्य-पुस्तकें भी करती हैं जो काली त्वचा को कुरूपता या बदसूरत या विकृति की भंगिमा के रूप में पेश करती हैं।

रंग को लेकर यह हमारी यह सोच पूर्वाग्रह मात्र नहीं है। यह एक किस्म का सांस्कृतिक जुनून है और उससे भी अधिक यह नस्लवाद का एक रूप है। हमारी रंगत अक्सर समाज में हमारे पदानुक्रम को भी जाहिर करती है। बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रवांडा एक ऐसा देश है, जिसकी पहचान जातीय दंगों, गरीबी और भयानक कुपोषण से जुड़ी हुई है। लेकिन हमें रवांडा से सीखना चाहिए कि किस तरह महिलाओं की राजनीतिक या संसदीय भागीदारी सुनिश्चित की जाए और किस तरह अपने देश को साम्राज्यवाद और बाजारवाद के प्रयोगों का अड्डा न बनने दिया जाए। इच्छाशक्ति हो तो क्या नहीं किया जा सकता!

जीत का रास्ता

भारतीय क्रिकेट टीम के सामने 2011 के विश्व कप के बाद से ही जो सबसे बड़ी समस्या रही है वह है नंबर चार का बल्लेबाज। यों तो इस स्थान के लिए बहुत से खिलाड़ियों को मौका मिला लेकिन कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया है। विश्व कप शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं इसलिए आइपीएल की फॉर्म, अनुभव और काबिलियत को देखते हुए भारतीय टीम में केएल राहुल, विजय शंकर और दिनेश कार्तिक को जगह मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरेगा!

केएल राहुल ने आइपीएल के दौरान सभी को प्रभावित किया है। राहुल का हाल-फिलहाल प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है। वहीं विजय शंकर ने भी बीते समय में भारतीय टीम के लिए बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। शंकर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर टीम को संतुलन दे सकते हैं। टीम में दूसरे विकेटकीपर और अनुभव के आधार पर दिनेश कार्तिक को भी जगह मिली है। दिनेश कार्तिक ने समय-समय पर अपने बल्ले का दम दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हो या निधास ट्रॉफी, जब-जब टीम को जरूरत पड़ी, तब तब उन्होंने रन बनाए हैं।

नंबर चार पर बल्लेबाजी करने कौन उतरेगा और उनका अंतिम एकादश क्या होगा, इसका फैसला जल्द ही करना होगा। अगर भारतीय टीम पूर्ण पांच गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरती है तो हो सकता है कि इन तीनों बल्लेबाजों में से किसी को भी मौका न मिले। ऐसे में टीम कुछ इस तरह हो सकती है- रोहित, धवन, विराट, धोनी, जाधव, पंड्या, भुवनेश्वर, शमी, कुलदीप, चहल और बुमराह। अगर भारतीय टीम एक ऑलराउंडर को और मैदान में उतारना चाहती है तो उसके पास जडेजा भी हैं। वे भुवनेश्वर या शमी की जगह टीम का हिस्सा बन सकते हैं।

विश्व कप में सभी टीमें जोश में दिख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफगानिस्तान सभी महज विश्व कप का हिस्सा बनने के लिए नहीं बल्कि जीतने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेंगे।

● *निशांत रावत, दिल्ली विश्वविद्यालय*

धर्म विरुद्ध

मथुरा में विदेशी श्रद्धालु को एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि उस श्रद्धालु ने राम-राम नहीं बोला था। इसी तरह दिल्ली के एक डॉक्टर को लड़कों के एक समूह ने जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया। इन दिनों कुछ लोग धार्मिक भावनाओं में बह कर ऐसी हरकतें करते हैं कि लगता है, उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं मालूम।

दरअसल, कोई भी धर्म गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। धर्म तो व्यक्ति को आत्मनियंत्रित, अच्छे काय करने, दूसरों की मदद करने, अन्य धर्मों का आदर करने या आत्मशुद्धि जैसे उच्च सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की शिक्षा देता है। लेकिन अब इसके विपरीत धर्म के नाम पर लोग हत्या तक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि वे अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म के प्रति हीन भावना रखते हैं। इस बुराई से ल्देशवासियों को उबारा जाना चाहिए।

● *संजू कुमार, चौबारा, हनुमानगढ़, राजस्थान*

विलुप्त होती प्रजातियां

यह बहुत दुखद है कि मनुष्य की बदनीयती, क्रूरता और लालच के कारण हमारे जैवमंडल से हर वर्ष कई वानस्पतिक व जैव प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में विलुप्तिकरण की यह दर और तेज हो जाएगी। विलुप्त हो चुके जीवों को वैज्ञानिक समुदाय अपनी लाख कोशिशों के बावजूद पुनर्जीवित नहीं कर सकता। प्रकृति अभी भी वैज्ञानिक बिरादरी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसलिए जैव मंडल को बचाने की कोशिशें बहुत ईमानदारी और संजीदगी से होनी चाहिए।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

युवाओं से छल

आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अच्छा रोजगार पाने की आशा में छात्र परिस्थिति व क्षमता के हिसाब से छोटी-बड़ी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं। बड़े-बड़े निजी और सरकारी महाविद्यालय भी इस प्रतिस्पर्धा के कारण अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए युवाओं को भविष्य सुरक्षित होने का वादा करके अपने यहां बड़ी मात्रा में प्रवेश दे रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की ओर से विद्यार्थी के पढ़ाई के अंतिम वर्ष के दौरान या पढ़ाई पूरी करते ही कैंपस से बड़ी कंपनी में नौकरी यानी 'प्लेसमेंट' दिलाने का प्रलोभन सबसे ज्यादा प्रचलन में है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए और युवा वर्ग को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में इसे एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है क्योंकि कुछ स्थानों पर युवाओं को इससे दीर्घकालिक लाभ मिलने के भी उदाहरण मिलते हैं लेकिन इसका प्रतिशत नगण्य ही है।

कैंपस प्लेसमेंट के दूसरे पहलू पर नजर डालने पर यह देखा जा रहा है कि कहीं-कहीं रोजगार के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरी के नाम पर उन्हें कम वार्षिक पैकेज का प्रस्ताव दिया जाता है। चुने जाने के बाद बच्चे पाते हैं कि वे ठगे गए हैं और उन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला है। इस बीच दूसरे विकल्पों को ठुकरा कर आए होने के कारण उनकी पीड़ा दुगुनी हो जाती है। यह पाया गया है कि विभिन्न बड़ी कंपनियों द्वारा 'जॉब' के नाम पर युवाओं का भविष्य एक निश्चित सीमा तक अनुबंध पत्र यानी 'बांड पेपर' के माध्यम से खरीद लिया जाता है। आवास और खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर बड़े-बड़े शहरों का सपना दिखा कर युवाओं को छला जाता है और जब यह सपना टूटता है तो उन्हें फिर अपने घर की ओर पलायन करना पड़ता है।

इस पूरे घटनाक्रम में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका पूरी तरह किंकर्तव्यविमूढ़ बनी रहती है। विद्यार्थियों-युवाओं को इस तरह की परिस्थिति से बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। रोजगार देने और नियुक्ति संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराना होगा। 'कैंपस प्लेसमेंट' आयोजित कराने वाली शैक्षिणक संस्थाओं की भी जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थी को चाहिए कि वे बिना जल्दबाजी दिखाए धैर्यपूर्वक नौकरी की शर्तों को भलीभांति पढ़ और संबंधित कंपनी की पृष्ठभूमि मालूम करके ही किसी भी प्रकार के लुभावने प्रस्ताव पर विचार करें।

● *ऋषभ देव पांडेय, कोरबा, छत्तीसगढ़*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com